विद्युत सागर में विद्युत के लिये कम पानी उपलब्ध होने और सतपुड़ा से मध्य प्रदेश द्वारा राजस्थान को पूरा हिस्सा न देने के कारण स्थिति बद से बदतर हो गई है।

दूसरी ओर कोटा अणु बिजलीघर की प्रथम इकाई 4 मार्च, 1982 से बन्द है। केन्द्र सरकार उसे सुधारने में अब तक असफल रही है। राजस्थान की प्रतिदिन आवश्यकता 210 लाख यूनिट के बदले में 80 से 90 लाख यूनिट बिजली प्राप्त हो रही है। प्रान्त के सभी उद्योगों में शत-प्रतिशत कटौती कर दी गई है। कृषि प्रयोजन के लिए 2-3 घंटे प्रतिदिन बिजली मिल रही है। पीने के पानी का संकट विशेषत: राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर में गंभीर रूप धारण कर रहा है। उद्योग एवं कृषि के क्षेत्र में राज्य के उद्योगपतियों और किसानों को करोड़ों रुपयों की हानि हुई है।

अत: केन्द्र सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि वे तुरन्त से तुरन्त अणु बिजली घर कोटा की दोनों इकाईयों को ठीक करावें और कोटा थर्मल प्लांट की प्रथम एवं द्वितीय इकाई को ठीक कराने में अपना सक्रिय सहयोग दे और सिंगरौली सुपर थर्मल प्लान्ट से अपने रिजर्व का पूरा हिस्सा और बदरपुर से अतिरिक्त बिजली और मध्य प्रदेश सरकार से सतपुड़ा से राज्य का हिस्सा और सरप्लस राज्यों से राजस्थान को विद्युत दिलाकर विद्युत के संकट से पार करावें।

(iii) Incidence of Small-port in various districts of U.P. and in Ranchi and other places in Bihar and meed to take remedial measures immediately..

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों तथा बिहार के रांची आदि अनेक स्थानों पर चेचक (माता) संक्रामक रोग की तरह फैलता जा रहा है जिससे सैकड़ों व्यक्तियों विशेषकर बच्चों की मृत्यु हो रही है। उ०प्र० के गोरखपुर देवरिया, बस्ती तथा लखनऊ के पास के इलाकों में फैली हुई इस भयंकर बीमारी की रोकथाम के लिए निकटतम ग्राम स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयां उपलब्ध नहीं है। इस बिमारी के प्रकोप से पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हैं। चेचक की इस बीमारी की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को दे दी गई है किन्तु इसे रोकने का कोई उपाय अभी तक नहीं किया गया है। यदि इस रोग को रोकने की दिशा में तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई तो इस रोग के और भी अन्य इलाकों में फैलने की आशंका है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस रोग पर तुरन्त काबू पाने के लिए शीघ्र से शीघ्र अपने चिकित्सा विशेषज्ञों को इस रोग से प्रभावित इलाकों में भेजकर जांच कराएं और इसे रोकने के लिए कारगर एवं ठोस कदम उठायें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चेचक इतनी भयंकर बीमारी है, जिसकी वजह से दो सौ से अधिक लोग मर चुके हैं। आपने इसको इतना लाइटली लिया है कि सिर्फ 377 के अन्तर्गत स्वीकृत किया है? इसको कालिंग अटेंशन में क्यों नहीं ले सकते ?

(iv) Need to take appropriate steps to increase production of pulses.

SHRI CHINTAMANI JENA (Balasore) : Sir; under Rule 377, I want to raise the following matter of urgent public importance.

In spite of the green revolution implemented by the Government, there has been a virtual stagnation in the output of pulses over the last ten years spanning two plan periods. Latest figures show that, the per hectare yield of pulses has remained at the same low levels as in the sixties. The production level of 13 millions tonnes achieved in 1975-76 has not been touched since then which resulted in the non-availability of main source of protien to the vast population. The *per capita* consumption has been declining from 50 gm. a day in 1976 to 38.4 gm in 1983.

The Agriculture Ministry concedes that pulses production has not been keeping pace with the advancement in technology and breakthrough in production in other cereals,

The suggestions of the experts to increase the production of pulses are (a) introduction of pulses crops in irrigated farming system, (b) bringing additional area under short duration moong and urd varieties in summer season, (c) intercropping of Arhar in both irrigated and un-irrigated conditions, (d) multiplication and use of improved pulse seeds, (e) use of phosphatic fertilisers and (f) suitable plant protection measures (g) improved post-harvest technology and price support.

According to the government's economic survey, the main reason for the low productivity of pulses in India, is the absence of improved technology and inputs comparable to those available for rice and wheat. Government's efforts to bring additional area under pulses have not been very successful.

In face of such very alarming situation, I would request the Agriculture Ministry to initiate appropriate time bound programme, providing for reasonable support prices for pulses and adoption of new technology by the farmers.

(v) Insanitary Conditions in Mathura City and in Vrindaban, Gokul, Baldev, etc. and need for inclusion of Mathura in the list of places pilgrimage.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मथुरा नगर से अधिक गन्दा नगर भारत में कदाचित कोई नहीं। मथुरा में 16 मार्च यमुना पुलिस सन्त सम्मेलन में जन समुदाय को सम्बोधित करते हुए सांसद श्रीमती शालिनी ताई पाटिल ने प्रश्न किया क्या मथुरा में म्युनिसिपैलिटी नहीं है या यहां के जन-प्रतिनिधि निष्क्रिय हैं ? श्रीमती पाटिल ने मथुरा नगर की गंदगी देखकर कहा "मैंने भारत के सभी तीर्थ देखे, सभी जगह सफाई मिली, किन्तु यहां सर्वत्र गन्दगी ही गन्दगी है। वहां डा० शंकरदयाल शर्मा, एम० पी० प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने भी मथुरा को प्रदूषण से प्रभावित बताया।

इसी प्रकार वृन्दावन, गोकुल, बल्देव, गोवर्धन, नन्दगांव, बरसाने आदि तीर्थ स्थानों की स्थिति है। अनेक बार आश्वासन देने पर भी मथुरा-वृन्दावन को तीर्थ स्थानों की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता। ताकि यहां की स्थिति में कुछ सुधार हो सके। चार वर्ष से अनेक बार लोक सभा में इस विषय को उठाने पर भी भारत सरकार ध्यान नहीं देती।

मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि इस समस्या को हल करने की शीघ्र कार्यवाही करे।

(vi) Need to take up Srisailam Project in Andhra Pradesh as a National Project.

SHRI PUCHALAPALLI PENCHALIAH (Nellore) : The first phase of Srisailam Dam over the river Krishna in Andhra Pradesh has been completed very recently. One unit of 110 MW is going to be commissionet very soon. Three more power units of 110 MW each are going to be commissioned under second phase. Even after completion of these two phases, about 1000 TMC water is expected to be surplus during monsoons. Even after the utilisation of surplus water by neighbouring States Karnatka and Maharashtra, Andhra Pradesh will still be in a position to make use of the surplus water of Krishna.

The Government of Andhra Pradesh has prepared a project report for generation of 1000 MW of power utilising the surplus waters. The cost of this proposed project is estimated to be Rs. 340 crores of which the Foreign Exchange component is only Rs. 10 crores. This Project report along with the necessary data has been submitted to the Government of India for its consideration.

In view of the power shortage not only in Andhra Pradesh, but also neighbouring States of Karnataka and Maharashtra, I request the Union Government to take up this project as a national project and take steps to execute it as early as possible.

(vii) Need for discussing with representatives of women's organisations the plan allocations for upliftment of women before finalising the Seventh Five year Plan.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay North Central): Sir, illiteracy among women and lack of vocational and professional training has rendered traditional skills of women in the modern industrialisation irrelevant. Labour laws enacted to protect women are not only observed more in violation, but have given an excuse to the employers to retrench women from the service. More and